Shri A. C. Guha: I think it was whether restriction of poppy cultivation has affected the supply of this chemical.

Dr. Satyawadi: Yes.

दिल्ली पुलिस बल

*९९२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली पुलिस बल में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं, और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) दिल्ली पुलिस में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :-

१९५०	२१९०
१९५१	१३१८
१९५२	७१०
१९५३	१३५५
१९५४	१२८४
१९५५	९०
	६९४७

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

१९५०	५०
१९५१	५३
१९५२	१८
१९५३	४७
१९५४	४५
१९५५	५
	२१८

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं जितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए निर्धारित है, ये आंकड़े उस की पूर्ति करते हैं ?

श्री दातार : नहीं ।

श्री नवल प्रभाकर : इसका कारण क्या है ?

श्री दातार : इसका कारण यह है कि योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिलते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत से लोगों को केवल उनकी जाति के आधार पर कि वे अनुसूचित जाति के हैं, इसी आधार पर उनको रिजैक्ट कर दिया जाता है ?

श्री दातार : नहीं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो आंकड़े अभी मंत्री महोदय ने दिये हैं, इन आंकड़ों के अनुसार कितने पुलिस में भर्ती होने वाले नौजवान देहली और कितने उत्तर प्रदेश और कितने पंजाब से अलग अलग से लिये गये हैं ?

श्री दातार: इस सब की जानकारी के लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री राधा रमण : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि.....

Mr. Speaker: Order, order. Let us go to the next question.

Reservation Rules

*994. **Shri I. Eacharan**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the suggestion made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to constitute a Committee for examining the reservation rules enforced by each Ministry has been approved by Government;

(b) if so, whether the Committee has been constituted; and

(c) if not, what are the difficulties in doing so?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): (a) to (c). Government have not considered it necessary to constitute a Committee for this purpose.

Shri I. Eacharan: What are the present arrangements to check up the proper implementation of these rules?

Shri Datar: Government have laid down a number of rules or concessions or rather relaxations of rules in this respect, and they are taking all possible steps to give concessions to these people; and therefore, no committee was considered necessary.

Dr. Rama Rao: The question is this. The posts reserved for Scheduled Castes are not being filled up by the various departments. Have Government set up any machinery to see why these posts are not being filled up?

Shri Datar: I am afraid the suggestion is not accurate. In fact, we are asking all the Ministries concerned to have an intake as large as possible. In some cases, candidates are not available; then, the reservation fixed is carried over to the next year, and is not allowed to lapse.

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

*९८५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री २, मार्च १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुसार विद्यार्थियों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या सरकार बता सकती है कि अब तक राज्य सरकारों ने इस मद में कितना खर्च किया है और उस में सेन्टर का क्या सहयोग रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इस सवाल के जवाब के लिये मैं सूचना मांग रहा हूं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : संविधान में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर राज्य १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करेंगी, लेकिन जिस गति से इस की प्रगति हो रही है उस के अनुसार क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि निश्चित अवधि के अन्दर संविधान की यह मंशा पूरी हो जाएगी ?

شکشا تتھا پراکرتک سنسادھن اور ویگیانک گویشنا منتری (مولانا آزاد): نہیں -اس کے لئے رسپانسیبل اسٹیٹ گورنمنٹ ہے -

[**The Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Maulana Azad)**: No, this is a responsibility of the State Governments.]

Shri K. K. Basu: May I ask a question?

Mr. Speaker: This is entirely a State subject. Next question.

STATISTICAL AND ECONOMIC ADVISORY SERVICE

*986. **Shri M. L. Agrawal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) since how long the proposals for constituting a "Statistical and Economic Advisory Service" has been under the active consideration of Government;

(b) whether they have been finalized; and

(c) if so, what are the provisions regarding recruitment, pay and allowances, and conditions of Service of Members of the Service?